

**The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE**

**Tuesday, 26 Nov , 2024**

**Edition: International Table of Contents**

<b>Page 01</b> <b>Syllabus : GS 2 : Indian Polity</b>	<b>'धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी' संविधान का अभिन्न अंग हैं, इन्हें प्रस्तावना में ही रहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया</b>
<b>Page 07</b> <b>Syllabus : Prelims Fact</b>	<b>कैबिनेट ने अटल मिशन के अगले चरण को मंजूरी दी</b>
<b>Page 09</b> <b>Syllabus : GS : 3 : Science and Technology</b>	<b>लद्दाख में MACE ने कॉस्मिक गामा किरणों के लिए अपनी अनूठी आंख खोली</b>
<b>Page 10</b> <b>Syllabus : GS 3 : Environment</b>	<b>पराली जलाने और सैटेलाइट डेटा पर</b>
<b>In News</b>	<b>भारत में युवा बेरोजगारी दर - वैश्विक स्तर से कम</b>
<b>Page 04 : Editorial Analysis:</b> <b>Syllabus : GS 2 : Indian Polity</b>	<b>संविधान अभी भी फल-फूल रहा है, इसे भारत को रास्ता दिखाने दें</b>

—It's about quality—

सर्वोच्च न्यायालय ने 1976 के 42वें संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को शामिल करने को बरकरार रखा, तथा संविधान को एक जीवंत दस्तावेज के रूप में महत्व दिया।

➡ इसने भारतीय संदर्भ में, विशेष रूप से राज्य कल्याण और धार्मिक तटस्थता के संबंध में उनके अर्थों को स्पष्ट किया।

## 'Secular, socialist' are an inalienable part of the Constitution, to stay in Preamble, orders SC

**Krishnadas Rajagopal**  
NEW DELHI

"The word 'secular' denotes a Republic that upholds equal respect for all religions. 'Socialist' represents a Republic dedicated to eliminating all forms of exploitation—whether social, political, or economic," a Bench of Chief Justice Sanjiv Khanna and Justice Sanjay Kumar interpreted.

The order was based on a batch of petitions filed in 2020, challenging the validity of the inclusion of 'socialist' and 'secular' in the Preamble through the 42nd Constitution Amendment in 1976. The petitioners, who included BJP leader Subramanian Swamy, argued that the insertions made with retrospective effect, that is from the date of adoption of the Constitution by the Constituent Assembly on November 26,

1949, amounted to a fraud on the Constitution. Besides, they argued that the word 'secular' was deliberately eschewed by the Constituent Assembly and the word 'socialist' fettered the economic policy choice of the elected government, which represents the will of the people.

The apex court, in its seven-page order, said the case was not worth a detailed adjudication as the flaws in the petitioners' arguments were manifest. Besides, the court found the motives of the petitions, filed nearly 44 years after such an insertion, "questionable".

The court held that the Preamble was an inalienable part of the Constitution. Parliament had an unquestionable power to amend the Constitution under Article 368.

Its amending extended to the Preamble. The court



confirmed the retrospective amendment to the Preamble, saying the date of adoption would not curtail the power under Article 368.

The court explained that the Constitution was a 'living document', and open to changes according to the needs of the time.

Though the Constituent Assembly was not sure about what 'secularism' should entail in India, the court said, over time, the nation has developed its own interpretation of the

term, which has become a basic feature of the Constitution.

"Over time, India has developed its own interpretation of secularism, wherein the State neither supports any religion nor penalises the profession and practice of any faith. This principle is enshrined in Articles 14, 15, and 16 of the Constitution, which prohibit discrimination against citizens on religious grounds while guaranteeing equal protection of laws and equal oppor-

tunity in public employment," the Supreme Court observed.

The court said the Preamble's original tenets of equality of status and opportunity, fraternity, dignity and liberty reflect the secular ethos of the Constitution.

The apex court clarified that 'socialism' in the Indian context meant the commitment to function as a welfare state.

"Neither the Constitution nor the Preamble mandates a specific economic policy or structure, whether left or right. Rather, 'socialist' denotes the state's commitment to be a welfare state and its commitment to ensuring equality of opportunity. India has consistently embraced a mixed economy model, where the private sector has flourished, expanded, and grown over the years," the apex court highlighted.

### प्रस्तावना में शामिल करने को चुनौती

- ➡ याचिकाओं के एक समूह ने 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को शामिल करने को चुनौती दी।
- ➡ याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 1949 में संविधान को अपनाने के बाद से पूर्वव्यापी रूप से शामिल किए गए ये शब्द असंवैधानिक थे तथा 'समाजवादी' शब्दों को शामिल करने से आर्थिक नीति विकल्प सीमित हो गए।

### सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

- ➡ सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को शामिल करना वैध था तथा संविधान का हिस्सा था।

- ➡ न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के तर्कों को त्रुटिपूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया तथा उनके उद्देश्यों पर सवाल उठाया, तथा मामला दायर करने में लगभग 44 वर्षों की देरी को नोट किया।

### प्रस्तावना और संविधान संशोधन

- ➡ प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, और संसद को अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन करने का अधिकार है।
- ➡ पूर्वव्यापी संशोधन को बरकरार रखा गया, जिसमें पुष्टि की गई कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जिसे बदलती जरूरतों के हिसाब से ढाला जा सकता है।

### 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्दों की व्याख्या

- ➡ 'धर्मनिरपेक्ष' की सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य किसी भी धर्म का समर्थन या भेदभाव नहीं करता है।
- ➡ यह सभी धर्मों के लिए समान सम्मान सुनिश्चित करता है और नागरिकों को अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने के अधिकार की गारंटी देता है।
- ➡ यह व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 पर आधारित है, जो धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं।
- ➡ ये प्रावधान कानून के तहत समान सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और सार्वजनिक रोजगार में समान अवसरों की गारंटी देते हैं, जो संविधान के धर्मनिरपेक्ष लोकाचार को मजबूत करते हैं।
- ➡ 'समाजवादी' की सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारत के संदर्भ में 'समाजवादी' का अर्थ है कल्याणकारी राज्य होने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता, अवसर की समानता और सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना।
- ➡ यह किसी विशिष्ट आर्थिक नीति को निर्धारित नहीं करता, चाहे वह वामपंथी हो या दक्षिणपंथी।
- ➡ यह शब्द संविधान के सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने और असमानता को दूर करने के लक्ष्य को दर्शाता है।
- ➡ भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाता है, जहाँ निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

### UPSC Mains PYQ : 2018

**Ques :** धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? चर्चा करें। (150 words/10m)

—It's about quality—

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2028 तक ₹2,750 करोड़ के बढ़े हुए आवंटन के साथ अटल इनोवेशन मिशन (AIM) को जारी रखने को मंजूरी दी। AIM 2.0 का उद्देश्य भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मज़बूत करना और सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, नवाचार और उच्च प्रभाव वाली सेवाओं को बढ़ावा देना है।

## Cabinet approves next phase of Atal Mission

**The Hindu Bureau**

NEW DELHI

The Union Cabinet, at a meeting here on Monday, approved the continuation of the Atal Innovation Mission (AIM), implemented by NITI Aayog, with an enhanced allocation of ₹2,750 crore for the period till March 31, 2028.

The Centre said the next

phase of AIM is expected to further enhance India's global competitiveness in the innovation ecosystem. "The continuation of AIM will directly contribute to creating better jobs, innovative products, and high-impact services across sectors," a release said.

It said AIM 2.0 will pilot new initiatives designed to fill gaps in the ecosystem.

### अटल इनोवेशन मिशन (AIM) अवलोकन:

- नीति आयोग द्वारा 2016 में शुरू किया गया AIM, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रमुख पहल है।
- इसका उद्देश्य स्कूलों में समस्या-समाधान और नवोन्मेषी मानसिकता की संस्कृति और विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और निजी क्षेत्र में उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।
- समग्र दृष्टिकोण में स्कूलों में अटल टिकरिंग लैब (ATL), विश्वविद्यालयों में इनक्यूबेशन सेंटर और वंचित क्षेत्रों में सामुदायिक नवाचार केंद्र स्थापित करना शामिल है।

### प्रमुख पहल:

- अटल टिकरिंग लैब्स (ATL):



## Daily News Analysis

- ○ भारत भर में 6वीं से 12वीं कक्षा के लिए 10,000 स्कूलों में स्थापित, जिसका उद्देश्य IoT, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स और मिनिचराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग करके जिज्ञासा और नवाचार को बढ़ावा देना है।
- ➡ **अटल इनक्यूबेशन सेंटर (AIC):**
  - ○ 72 केंद्र 3500 से अधिक स्टार्टअप का समर्थन करते हैं, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मेंटरशिप, फंडिंग और तकनीकी सुविधाएँ प्रदान करते हैं।
  - ○ हेल्थटेक, एडटेक, फिनटेक, स्पेसटेक और अन्य क्षेत्रों में स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करें।
- ➡ **अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र (ACIC):** नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कम सेवा वाले क्षेत्रों को लक्षित करना।
- ➡ **AIM प्रभाव:** रोजगार सृजन, उद्यमिता को बढ़ावा देना और नवाचार में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।

लद्दाख के हानले में मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनकोव एक्सपेरीमेंट (MACE) दूरबीन दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरनकोव दूरबीन है, जो गामा-रे खगोल विज्ञान में भारत की भूमिका को आगे बढ़ाती है।

- यह उच्च-ऊर्जा ब्रह्मांडीय घटनाओं का अध्ययन करता है और डार्क मैटर कणों की खोज करता है।
- स्वदेशी रूप से निर्मित, यह उच्च-ऊर्जा खगोल भौतिकी और कण भौतिकी अनुसंधान में भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करता है।

## MACE in Ladakh opens its one-of-a-kind eye to cosmic gamma rays

MACE's main goal is to study gamma rays with more than 20 billion eV of energy; the telescope can examine gamma rays emitted from beyond the Milky Way; other potential targets include pulsars and blazars; it will also be used to explore a class of hypothetical dark-matter particles

Shreejaya Karantha

**T**he Major Atmospheric Cherenkov Experiment (MACE) telescope is a state-of-the-art ground-based gamma-ray telescope inaugurated in Hanle, Ladakh, on October 4. Located at around 4.3 km above sea level, it is the highest imaging Cherenkov telescope in the world. It boasts of a 21-metre-wide dish, the largest of its kind in Asia and second-largest in the world.

The facility was built by the Bhabha Atomic Research Centre, the Tata Institute of Fundamental Research, the Electronics Corporation of India Ltd., and the Indian Institute of Astrophysics.

Light comes in a wide range of wavelengths but humans can only see a small portion. In the electromagnetic spectrum, gamma rays have the shortest wavelength and the highest energy, with each light-particle possessing more than 100,000 electron volts. (Visible-light photons have around 1.63-3.26 eV each.)

### A strange blue light

Gamma rays are produced by exotic energetic objects in the cosmos, including rapidly spinning pulsars, supernova explosions, hot whirlpools of matter around black holes, and gamma-ray bursts. Because of their high energy, gamma rays are a health hazard. They can damage living cells and may even trigger deleterious mutations in DNA. Fortunately, the earth's atmosphere blocks gamma rays from reaching the ground. Thus, astronomers who want to study objects that emit gamma rays prefer using space observatories – although there are indirect techniques to detect gamma rays with very high energies from the ground.

When a gamma ray from a cosmic source enters the atmosphere, it interacts with molecules in the air to produce a copious shower of electron-positron pairs. As these charged particles travel through the atmosphere at speeds greater than the speed of light in air, they emit a faint blue light, called Cherenkov radiation. This radiation has wavelengths typical of violet and blue light of the visible spectrum and of the ultraviolet wavelength range.

The light is emitted in about a fraction of a second, and the light particles spread out evenly over a vast region on the earth's surface. This region is a suitable place to locate a detector that can collect the photons and study them to indirectly understand the gamma rays. Instruments used for this kind of detection are called imaging atmospheric Cherenkov telescopes (IACTs). The MACE telescope is an IACT.

### Strength in numbers

Every IACT has a light collector and a camera. The size of the light collector determines the minimum energy of gamma rays it can detect. MACE's light collector has 356 mirror panels. Each panel consists of four smaller mirrors arranged in a honeycomb structure. These honeycomb arrangements have been shown to be lighter yet more stable than solid mirrors because they reduce the empty space between segments and increase the total reflective area. The James Webb Space Telescope uses honeycomb-segmented mirrors for this reason.

To ensure it can detect gamma rays in the required energy range, MACE's



The blue spot at the centre of the red ring is an isolated neutron star in the Small Magellanic Cloud. Neutron stars are formed after heavy stars go supernova, in the process emitting gamma rays alongside radiation at other energies. ESA/NASA

construction and its geographical location were carefully planned. The high-altitude location puts the telescope above disturbances in the lower reaches of the troposphere. MACE is also not housed in a dome because of its large size, leaving its mirrors continuously exposed to the environment. Each mirror is coated with a thin layer of silicon dioxide for protection.

The mirrors are aligned to collect and focus the Cherenkov radiation into the high-resolution camera, which is made up of 1,088 photomultiplier tubes that detect the faint signals and amplify them. All the necessary electronic components for processing and recording data are placed within the camera, including a specialised device that continuously converts signals from photomultiplier tubes into digital data, allowing computers to perform real-time analysis.

The telescope has a moving weight of 180 tonnes. It stands on a base with six wheels that roll along a 27-metre-wide curved track. The drive system that moves the telescope uses an altitude-azimuth mount, meaning the telescope can shift its gaze both vertically and horizontally, to observe all patches of the sky.

MACE's main goal is to study gamma rays with more than 20 billion eV of

**Gamma rays are produced by exotic energetic objects in the cosmos, including rapidly spinning pulsars, supernova explosions, hot whirlpools of matter around black holes, and gamma-ray bursts**

energy. The telescope can examine high-energy gamma rays emitted from near black holes beyond the Milky Way and which are digesting large volumes of matter. Other potential astrophysical targets include gamma-ray pulsars, blazars, and gamma-ray bursts.

One important goal is to find dark matter particles. Dark matter is a type of matter believed to make up more than 85% of the total mass in our universe. It is a fundamental part of the standard model of cosmology – but scientists don't know what subatomic particles it could be made of.

One of the proposed particle constituents of dark matter is weakly interacting massive particles (WIMPs). Scientists have predicted that these particles can produce high-energy gamma rays when they collide into and destroy each other.

These gamma rays could be produced

in large galaxy clusters, small galaxies, and/or the centre of large galaxies, including the Milky Way.

### India's MACE is the next step

Previous studies have shown that the MACE telescope can help find and measure the high-energy gamma rays produced by WIMPs. This will allow astronomers to learn more about dark matter and the behaviour of WIMPs. But just as likely, MACE could help verify whether WIMPs actually exist and make up dark matter or whether this hypothesis is flawed.

India has been active in gamma-ray astronomy for more than five decades now. The unveiling of the MACE telescope marked a significant step towards further technological and scientific advancements in the field. Most of MACE's subsystems were also built and designed within the country.

With its advanced capabilities, MACE could play an important role in addressing fundamental open questions in the field of high-energy astrophysics and particle physics, and pave the way for cutting-edge research. (Shreejaya Karantha is a freelance science writer and a content writer and research specialist at The Secrets of The Universe. shreejayakaranta@gmail.com)

## गामा किरणों का महत्व

- गामा किरणें, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक ऊर्जा वाली रोशनी हैं, जो पल्सर, ब्लैक होल और सुपरनोवा जैसी ब्रह्मांडीय घटनाओं द्वारा उत्पन्न होती हैं।

## Daily News Analysis

- ➡ ये किरणें पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अवरुद्ध होती हैं, जिससे अप्रत्यक्ष भू-आधारित पता लगाना महत्वपूर्ण हो जाता है।
- ➡ जब गामा किरणें वायुमंडल के साथ संपर्क करती हैं, तो वे चरेनकोव विकिरण उत्पन्न करती हैं, एक हल्का नीला प्रकाश जिसे MACE पहचानता है।

### MACE टेलीस्कोप का अवलोकन

- ➡ **स्थान और ऊँचाई:** लद्दाख के हानले में 4.3 किमी की ऊँचाई पर स्थित, यह दुनिया की सबसे ऊँची इमेजिंग चरेनकोव दूरबीन है।
- ➡ **आकार और विशेषताएँ:** इसमें 21 मीटर चौड़ी डिश है, जो एशिया में सबसे बड़ी और विश्व स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी है।
- ➡ **प्रौद्योगिकी और घटक:** 356 हनीकॉम्ब-स्ट्रक्चर्ड मिरर पैनल और 1,088 फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब के साथ एक उच्च-रिज़ॉल्यूशन कैमरा से लैस है।
- ➡ **निर्माण और सहयोग:** BARC, TIFR, ECIL और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा निर्मित, स्वदेशी क्षमताओं का प्रदर्शन।
- ➡ **वैज्ञानिक लक्ष्य:** 20 बिलियन से अधिक eV ऊर्जा वाली गामा किरणों का अध्ययन करना और ब्लैक होल, पल्सर और डार्क मैटर जैसी ब्रह्मांडीय घटनाओं की खोज करना।
- ➡ **उन्नत यांत्रिकी:** इसमें 180 टन का मूविंग वेट है और यह सटीक आकाश अवलोकन के लिए 27 मीटर चौड़े घुमावदार ट्रैक पर काम करता है।
- ➡ **महत्व:** भारत के गामा-रे खगोल विज्ञान और उच्च-ऊर्जा खगोल भौतिकी अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण कदम है।

### वैज्ञानिक लक्ष्य

- ➡ MACE 20 बिलियन eV से अधिक ऊर्जा वाली गामा किरणों का अध्ययन करता है, जो ब्लैक होल, पल्सर और गामा-रे बर्स्ट जैसी घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है।
- ➡ इसका उद्देश्य WIMP जैसे डार्क मैटर कणों की खोज करना है, जो संभावित रूप से आकाशगंगा के केंद्रों और समूहों में उत्पन्न होते हैं।

### भारत का मील का पत्थर

- ➡ MACE दूरबीन गामा-रे खगोल विज्ञान में भारत की पाँच दशक लंबी यात्रा को आगे बढ़ाती है।
- ➡ इसकी स्वदेशी डिज़ाइन और क्षमताएँ भारत को उच्च-ऊर्जा खगोल भौतिकी और कण भौतिकी अनुसंधान में अग्रणी बनाती हैं।

### UPSC Mains Practice Question

**Ques :** MACE दूरबीन के महत्व और डार्क मैटर और गामा किरणों जैसी ब्रह्मांडीय घटनाओं को समझने में इसकी क्षमता पर चर्चा करें। (150 Words /10 marks)

It's about quality



**Page 10 : GS 3 : Environment – Environment pollution and degradation**

दिल्ली में वायु गुणवत्ता दीपावली के बाद भी खराब बनी हुई है, बावजूद इसके कि कई उपाय किए गए हैं।

- ➔ पंजाब और हरियाणा में धान की पराली जलाना, जिसका नासा के उपग्रहों के माध्यम से पता लगाया गया, इसका एक बड़ा कारण है।
- ➔ देरी से पराली जलाने को लेकर विवाद हुआ, ताकि पता न चल सके, जिससे डेटा की सटीकता को चुनौती मिली और वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों में कमियों को उजागर किया गया।

## On stubble burning and satellite data

How are satellites used to track farm fires resulting from the stubble burning in Punjab and Haryana? What are the satellites used and how effective are they? Have the farmers worked their way around the tracking methodology?

### EXPLAINER

Vasudevan Mukunth

#### The story so far:

The air quality in the national capital has been struggling to recover from the lows to which it dropped right after Deepavali despite the implementation of GRAF stage IV measures, the active intervention of the Supreme Court, and stop-gap measures by the Delhi government. Many fingers are currently pointed at the farm fires in the surrounding States, where farmers are burning paddy stubble in time for the wheat-sowing season. While these fires are not solely responsible for Delhi's plight, a controversy over measuring their prevalence illustrates the amount of attention they are receiving.

#### How are the fires counted?

Farmers in Punjab and Haryana sow rice in the kharif season and harvest it in November, using the summer monsoons to quench the crop's high water demand. After the rice is harvested, they need to clear the leftover organic material—called paddy stubble—in order to make way for the next sowing season. For reasons of time and cost, they have traditionally preferred to burn the stubble. But thanks to the winds at this time of the year over the National Capital Region, the toxic particulate matter from the fires is floated to and hangs over New Delhi, dragging its air quality down.

Because of the large area over which farmers light the fires, officials have said satellites are the best way to track the fires. The Indian government currently procures this data from two NASA satellites called Aqua and Suomi-NPP. NASA launched Aqua in 2002 and it is currently in the twilight stage of its designed lifespan. Its Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) instrument was built to track changes in the lower atmosphere, especially over land, through time. MODIS's technical successor is the Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) instrument onboard Suomi-NPP, which NASA launched in 2011. Both satellites are part of NASA's 'Earth Observing System'.

Aqua's and Suomi-NPP's overpass at each location happens at 1:30 p.m. local time in the day and at 1:30 a.m. local time at night. Their MODIS and VIIRS instruments collect visible and infrared images of the earth at around these intervals and are capable of spotting fires and smoke in a small window centred on the overpass time. The Ozone Mapping and Profiler Suite onboard Suomi-NPP can also identify aerosol loads in the atmosphere, which is useful to track smoke from fires and their eventual contribution to air pollution.

#### What is the new controversy?

On October 2, a senior scientist at NASA's Goddard Space Flight Centre named Hiren Jethva wrote on X (Twitter) that there were 40% fewer farm fires than predicted in 2023 and expressed hope for the trend to continue this year. On October 24, Mr. Jethva wrote in the same thread that the number of fires in 2024 seemed to be the "fewer in [the] last decade", and added that either "ground efforts to curb residue-burning appear to be working or burning activities [are] taking place after satellite overpass time, but it needs ground-truthing".

His post implied farmers were burning paddy stubble after the Aqua and



**Billowing trouble:** Stubble being burnt at a paddy field on the outskirts of Amritsar in Punjab earlier this month. PTI

Suomi-NPP satellites had completed their overpass at around 1:30 p.m.

The next day Jethva followed up by comparing data from Aqua and Suomi-NPP with data from the GEO-KOMPSAT 2A satellite. South Korea launched this satellite, also called Cheollian 2A, in 2018 as a "dedicated geostationary weather satellite"; it's currently stationed at 128.2° E and has a planned mission life of at least a decade.

In the visuals Mr. Jethva collected and presented from the three satellites, the smoke cover over cropland in Punjab and Haryana seemed to thicken after Aqua and Suomi-NPP had completed their overpass, as if farmers were lighting more fires later in the day from before.

The senior scientist also wrote that the quantity of aerosols in the air was roughly the same as in previous years whereas it should have been lower given Aqua and Suomi-NPP indicated there were fewer fires.

#### Is the discrepancy real?

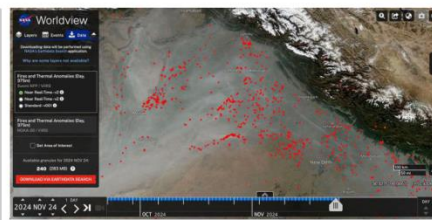
In 2020, the Indian government created the Commission for Air Quality Management in the NCR and Adjoining Areas (CAQM for short) by ordinance and a subsequent Act of Parliament in 2021. Its mandate was to study, identify, and resolve issues relevant to improving air quality in its jurisdiction.

On Saturday, *The Hindu* reported based on multiple sources and documents that the CAQM was aware farmers were burning paddy stubble after the NASA satellites had completed their overpass to avoid being detected. However the CAQM has continued to insist in the public that the number of farm fires has dropped, defending its conclusion in the face of contrary evidence by claiming it used different formulae.

That farmers were aware of the overpass timings is recorded in the minutes of a March 7, 2024, meeting, where director of Haryana Space Applications Centre Sultan Singh and National Remote Sensing Centre (NRSC) scientist Bhavana Sahay alleged as much. Farmers on the ground also told *The Hindu* a government official had asked them to light fires after 4 p.m.

(The alleged advice echoes Goodhart's law: "when a measure becomes a target, it ceases to be a good measure".)

The CAQM has also come under the



pump from a second angle: in affidavits to the Supreme Court, it has said the burnt area in Punjab shrank 26.5% between 2022 and 2023 whereas data from the Government of Punjab and the Indian Agricultural Research Institute, which is funded by the Centre, says it increased 24% and 15% respectively.

#### How is the government responding?

The Centre had originally created the CAQM to replace the Environmental Pollution (Prevention and Control) Authority (EPCA), which the Supreme Court had created in 1998. EPCA was a non-statutory body and lacked the instruments to sanction non-compliant actors. CAQM was designed to have teeth in the 2021 Act – and which it has since been accused of not wielding.

The Supreme Court in particular has upbraided the CAQM for failing to mitigate air pollution resulting from the fires over the years. The body was expected to respond on November 25 to the Supreme Court to allegations that it was aware farmers were delaying burns to after the satellites' overpass. The Indian government is also on the back foot after Union Agriculture Minister Shri Raj Singh Choudhan said on October 26 that the number of stubble-burning incidents have dropped this year.

But the CAQM has also maintained that its efforts have lowered the prevalence of fires by 71% in Punjab and 44% in Haryana between 2020 and 2024, and has objected to the idea of a group of retired judges overseeing the fight against stubble-burning.

The CAQM also said it wrote to the NRSC – a body under the Indian Space

### THE GIST

Because of the large area over which farmers light the fires, officials have said satellites are the best way to track the fires. The Indian government currently procures this data from two NASA satellites called Aqua and Suomi-NPP.

While satellite data showed that there was a reduction in farm fires, the smoke cover over cropland in Punjab and Haryana seemed to thicken after the satellites had completed their overpass and the quantity of aerosols in the air was roughly the same as in previous years.

The Commission for Air Quality Management in the NCR and Adjoining Areas was expected to respond on November 25 to the Supreme Court to allegations that it was aware farmers were delaying burns to after the satellites' overpass.

Research Organisation (ISRO) – asking it to develop a standard protocol to measure burnt area in January 2024. At present, burnt area data is available once every five days from the Sentinel II satellites of the European Space Agency.

#### Can Indian satellites help?

In an affidavit to the Supreme Court on November 21, the CAQM said ISRO plans to evaluate the usability of data from various satellites to identify farm fires. According to the affidavit, ISRO experts are of the view that data from INSAT-3DR (by India), GEO-KOMPSAT 2-AMT (South Korea), Meteosat 9, Feng Yun-4A/4B (China), and HIMAWARI-8 (Japan) cannot provide accurate fire counts – although their assessments will not be complete for at least another month.

The problem with INSAT-3DR is that its data is too coarse: of 1 km in visible and short-wave infrared radiation, of 4 km in middle and thermal infrared, and of 8 km for water vapour. In August 2021, ISRO had launched another satellite that could have been useful in this context, GISAT-1, but the GSLV-F10 mission carrying it failed after the rocket's upper stage failed to fire.

ISRO also operates the three RESOURCESAT satellites, launched in 2003, 2011, and 2016, with similar payloads. Those in RESOURCESAT 2A have better features, however. The Linear Imaging Self Scanner (LISS) cameras 3 and 4, both of which 'see' in visible and near-infrared radiation; LISS-4 has a spatial resolution of 5.8 m and LISS-3, of 23.5 m. The Advanced Wide Field Sensor (AWIFS) camera detects similar radiation at an even lower resolution of 36 m.



### दीपावली के बाद दिल्ली में वायु गुणवत्ता संकट

- GRAP चरण IV उपायों, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और दिल्ली सरकार की कार्रवाई के बावजूद, दीपावली के बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब बनी हुई है।
- पंजाब और हरियाणा में खेतों में आग लगना, जहाँ गेहूँ की बुवाई के लिए धान की पराली जलाई जाती है, प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- हालाँकि ये पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन वायु गुणवत्ता पर इनके गंभीर प्रभाव के कारण इन आग की जाँच की जा रही है।

### उपग्रहों का उपयोग करके खेतों में आग लगने पर नज़र रखना

- **धान की पराली जलाना:** समय और लागत की कमी के कारण किसान गेहूँ की बुवाई की तैयारी के लिए चावल की कटाई के बाद पराली जलाते हैं।
- **नासा के उपग्रह:** भारत खेतों में आग लगने पर नज़र रखने के लिए एक्का और सुओमी-एनपीपी उपग्रहों से डेटा का उपयोग करता है।
  - 2002 में लॉन्च किया गया एक्का वायुमंडलीय परिवर्तनों की निगरानी के लिए MODIS उपकरण का उपयोग करता है।
  - 2011 में लॉन्च किया गया सुओमी-एनपीपी, आग और धुएँ का पता लगाने के लिए VIIRS उपकरण और एरोसोल ट्रैकिंग के लिए ओजोन मैपिंग प्रोफाइलर सूट का उपयोग करता है।
  - दोनों उपग्रह स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे और सुबह 1:30 बजे स्थानों के ऊपर से गुजरते हैं, और दृश्यमान और अवरक्त छवियों को कैप्चर करते हैं।

### सैटेलाइट डेटा पर उभरता विवाद

- NASA के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने 2024 में कम आग लगने की घटनाओं को नोट किया, लेकिन सैटेलाइट के ओवरपास समय के बाद जलने की संभावना पर प्रकाश डाला।
- दक्षिण कोरिया के GEO-KOMPSAT 2A उपग्रह के साथ तुलना करने पर पता चला कि एक्का और सुओमी-एनपीपी के दैनिक गुजरने के बाद धुआँ बढ़ रहा है।
- वायुमंडल में एरोसोल का स्तर पिछले वर्षों के अनुरूप बना हुआ है, जो आग लगने की घटनाओं में कमी के दावों का खंडन करता है।

### रिपोर्टिंग और डेटा में विसंगति

- **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM):**
  - एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2020 में स्थापित किया गया।
  - आरोप सामने आए कि किसानों को उपग्रह की पहचान से बचने के लिए ओवरपास के बाद पराली जलाने की सलाह दी गई थी।
- पंजाब और IARI की रिपोर्टें जले हुए क्षेत्रों में वृद्धि दर्शाती हैं, जो CAQM के 26.5% कमी के दावे का खंडन करती हैं।
- **गुडहार्ट का नियम:**
  - बताता है कि जब उपायों को लक्ष्य बना दिया जाता है तो वे कैसे प्रभावी नहीं रह जाते।
  - पराली जलाने के समय में हेरफेर करने वाले किसान इस सिद्धांत को दर्शाते हैं: उपग्रह की पहचान से बचने के उद्देश्य से, वे व्यवहार को समायोजित करते हैं, जिससे आग को ट्रैक करने और प्रदूषण को संबोधित करने में उपाय की विश्वसनीयता कम हो जाती है।

### सरकार की प्रतिक्रिया और चुनौतियाँ

- **सुप्रीम कोर्ट की आलोचना:** पराली जलाने और वायु प्रदूषण को कम करने में CAQM की अप्रभावीता के लिए आलोचना की गई है।
- **CAQM का दावा:** 2020 और 2024 के बीच पंजाब में 71% और हरियाणा में 44% कमी का दावा किया गया।
  - NRSC और ISRO के सहयोग से सटीक उपग्रह प्रोटोकॉल विकसित करने के प्रयास चल रहे हैं।

### भारतीय उपग्रह और सीमाएँ

- **INSAT-3DR:** आग का सटीक पता लगाने के लिए अनुपयुक्त मोटे-रिज़ॉल्यूशन डेटा प्रदान करता है।

## Daily News Analysis

- ➡ **RESOURCESAT उपग्रह:** LISS और AWiFS जैसे उपकरणों के साथ बेहतर स्थानिक रिज़ॉल्यूशन प्रदान करते हैं, लेकिन फिर भी सीमाएँ हैं।
- ➡ GISAT-1: योगदान दे सकता था, लेकिन 2021 में अपने प्रक्षेपण के दौरान विफल रहा।

### निष्कर्ष

- ➡ खेतों में आग को लेकर विवाद दिल्ली की आवर्ती वायु गुणवत्ता संकट को कम करने के लिए सटीक माप प्रणाली और कार्रवाई योग्य समाधानों की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है।
- ➡ बढ़ी हुई तकनीक और अंतर-एजेंसी समन्वय महत्वपूर्ण हैं।

### UPSC Mains PYQ : 2015

**Ques :** मुंबई, दिल्ली और कोलकाता देश के तीन बड़े शहर हैं, लेकिन दिल्ली में वायु प्रदूषण अन्य दो शहरों की तुलना में कहीं ज़्यादा गंभीर समस्या है। ऐसा क्यों है? (200 words/12.5m)



**In News : भारत में युवा बेरोजगारी दर – वैश्विक स्तर से कम**

भारत के रोजगार परिदृश्य में सुधार दिख रहा है, वैश्विक स्तर की तुलना में 2023-24 में युवा बेरोजगारी घटकर 10.2% रह गई है।

- श्रमिक जनसंख्या अनुपात में वृद्धि हुई है, और नौकरियों का औपचारिकीकरण महत्वपूर्ण EPFO नामांकन के माध्यम से स्पष्ट है। सरकारी योजनाएँ रोजगार सृजन और कौशल विकास को प्राथमिकता देती हैं।



**युवा बेरोजगारी: वैश्विक बनाम भारत**

- मानव विकास संस्थान (IHD) और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा भारत रोजगार रिपोर्ट, 2024, वैश्विक स्तर की तुलना में भारत में बेहतर युवा रोजगार पर प्रकाश डालती है।
- ILO रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर, 2021 में युवा बेरोजगारी दर 15.6% और 2023 में 13.3% थी।
- भारत में, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2023-24 ने 10.2% की युवा बेरोजगारी दर (15-29 वर्ष की आयु) की रिपोर्ट की, जो वैश्विक औसत से काफी कम है।

**प्रमुख श्रम बल संकेतक**



## Daily News Analysis

- ➡ **श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR):** 2017-18 में 31.4% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गया, जो युवाओं में रोजगार की अधिकता को दर्शाता है।
- ➡ **EPFO पेट्रोल डेटा:** 2023-24 में 1.3 करोड़ से अधिक शुद्ध ग्राहक EPFO में शामिल हुए, जिसमें सितंबर 2017 और अगस्त 2024 के बीच 7.03 करोड़ शुद्ध ग्राहक जुड़े, जो औपचारिक रोजगार में वृद्धि को दर्शाता है।

### रोजगार सृजन के लिए सरकारी पहल

- ➡ रोजगार सृजन और रोजगार क्षमता बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है।
- ➡ प्रमुख योजनाओं में शामिल हैं:
  - प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)।
  - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS)।
  - प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)।
  - दीन दयाल अंत्योदय योजना (DAY-GKY और DAY-NULM)।
  - इन योजनाओं को MSME, ग्रामीण विकास, आवास और शहरी मामलों और वित्त जैसे मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

### UPSC Mains PYQ : 2022

**Ques :** कल्याणकारी योजनाओं के अलावा, भारत को समाज के गरीब और वंचित वर्गों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के प्रबंधन की भी आवश्यकता है। चर्चा करें।(250 words/15m)

**Page : 04 Editorial Analysis**

# *The Constitution still thrives, let it show India the way*

**T**his month marks the 75th anniversary of the adoption by the Constituent Assembly of the draft Constitution of India, on November 26, 1949. The Union government has announced that it intends to commemorate this momentous occasion with a special joint sitting of Parliament. There are bound to be several self-congratulatory speeches, from all sides of our fractious political divide. But the speech that should haunt us all is that of the principal draftsman of the Constitution, B.R. Ambedkar, on the eve of the Constitution's adoption. On November 25, 1949, in his magisterial summation of the work of the Drafting Committee he chaired, and before commending its work to the Assembly, he pointedly observed: "however good a Constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it, happen to be a bad lot. However bad a Constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it, happen to be a good lot."

The working of the Constitution, Dr. Ambedkar pointed out, depended on how the people and the political parties applied it. The drafters had made provision for relatively easy amendment, so as to permit the document to keep up with the needs of the times. But the rest depended on the way successive generations of its custodians chose to implement it.

**The lacunae that B.R. Ambedkar identified**  
Dr. Ambedkar highlighted the fact that "there is complete absence of two things in Indian society" – equality and fraternity. "On the 26th of January 1950," he declared, "we are going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality. In politics we will be recognizing the principle of one man one vote and one vote one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man one value. How long shall we continue to live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life?"

In calling for a social and not merely political democracy to emerge from the Constitution, Dr. Ambedkar stressed the absence of fraternity as the second major ingredient that was missing in India. "Fraternity means a sense of common brotherhood of all Indians – of Indians being one people. It is the principle which gives unity and solidarity to social life." But thanks to the caste system – the entire structure of caste, he averred,



**Shashi Tharoor**

a fourth-term Indian National Congress Member of the Lok Sabha for Thiruvananthapuram, and the award-winning author of 26 books, including 'The Battle of Belonging: On Nationalism, Patriotism and What it Means to be Indian' (2021). He is a member of the Congress Working Committee

But a speech that should haunt all Indians is that of its principal draftsman on the eve of the Constitution's adoption – on people and political parties making it work

was 'anti-national' – religious divisions and the absence of a common sense of nationhood among some Indians, fraternity had not yet been achieved. But it was indispensable, since liberty, equality and fraternity were all intertwined and could not flourish independently of one another. "Without equality," he pointed out, "liberty would produce the supremacy of the few over the many. Equality without liberty would kill individual initiative. Without fraternity, liberty would produce the supremacy of the few over the many. Without fraternity, liberty and equality could not become a natural course of things. It would require a constable to enforce them."

## **What has changed**

Today, 75 years later, it is well worth asking what progress we have made to achieve the aims of the Constitution's drafters, and in particular to fill the lacunae that Dr. Ambedkar identified. Equality has advanced, no doubt, with the abolition of untouchability being accompanied by the world's oldest and farthest-reaching affirmative action programme, in the form of reservations, initially for Scheduled Castes and then for the Other Backward Classes (OBC). These reservations, which were initially intended to be temporary, have now been entrenched in our system and may be said to be politically unchallengeable. But the task of promoting social and economic equality, which Dr. Ambedkar pointed to, is far from complete. The clamour for further opportunities for those who believe that Indian society continues to deny them the equality of outcomes that the numbers warrant, continues to roil our politics. The escalating demand for a caste census is bound to have further implications for the evolution of India's constitutional practice.

As for fraternity, the mobilisation of votes in our contentious democracy in the name of caste, creed, region and language have ensured that the social and psychological sense of oneness that Dr. Ambedkar spoke about, is still, at best, a work in progress. But there is no doubt that the sense of nationhood that he felt had not yet come into existence has now become embedded across the country. One only needs to look at the crowds at a cricket match involving the Indian team, or the national outrage and mourning after an international conflict such as the Kargil war (1999) or the Galwan incident (2020), to be aware that there is a strong sense of nationhood despite the persistence of local or sectarian identities.

Yet, by reifying caste reservations, India has promoted equality but arguably undermined fraternity. Fraternity had a special place in Dr. Ambedkar's vision; the word was, in many ways, his distinctive contribution to India's constitutional discourse. It also had an economic dimension, with the implicit idea that the assets of the better-off would be used to uplift the untouchables and other unfortunates. Fraternity would both result from and lead to the erosion of social and caste hierarchies. But, as the sociologist Dipankar Gupta has argued, the extension of reservations to the OBCs saw caste as 'an important political resource to be plumed in perpetuity'.

Professor Gupta avers that this 'is not in the spirit of enlarging fraternity, as the Ambedkar proposals are'; while Dr. Ambedkar's ultimate aim was the annihilation of caste from Indian society, for Mandal, caste was not to be "removed", but to be "represented". It entrenched caste rather than eliminating it from public life.

## **Highs and worrying lows**

This debate may well go on. Still, we can be grateful that the ascent to power of the very elements of Indian politics who had initially rejected the Constitution has not resulted in its abandonment. There is a certain irony to a Bharatiya Janata Party government celebrating a document that its forebears in the Rashtriya Swayamsevak Sangh and the Jana Sangh had found "un-Indian" and devoid of soul. That soul has evolved over 75 years and 106 amendments, and the Constitution still thrives. But the hollowing out of many of the institutions created by the Constitution, the diminishing of Parliament, pressures on the judiciary and the undermining of the democratic spirit – leading to the V-Dem Institute labelling India as an "electoral autocracy", policed by the "constable" Dr. Ambedkar warned against – mean that much still remains to be done by its custodians.

"Independence," Dr. Ambedkar said in concluding his memorable speech, "is no doubt a matter of joy. But let us not forget that this independence has thrown on us great responsibilities. By independence, we have lost the excuse of blaming the British for anything going wrong. If hereafter things go wrong, we will have nobody to blame except ourselves." Seventy-five years later, let us vow to reduce the number of things we need to blame ourselves for – and let the Constitution show us the way.



**GS Paper 02 : भारतीय राजव्यवस्था**

**UPSC Mains Practice Question:** चर्चा करें कि भारत में समकालीन सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में डॉ. बी.आर. अंबेडकर का समानता और बंधुत्व का दृष्टिकोण किस प्रकार प्रासंगिक है। (150 Words /10 marks)

### Context :

- यह लेख भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर विचार करता है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के साथ राजनीतिक समानता के बारे में डॉ. बी.आर. अंबेडकर की चिंताओं पर प्रकाश डाला गया है।
- यह जाति-आधारित विभाजन और संस्थागत कमजोरियों सहित लगातार चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समानता और भाईचारा प्राप्त करने में प्रगति की जांच करता है।
- विकासशील सामाजिक-राजनीतिक गतिशीलता के बीच संविधान की लचीलापन पर जोर दिया गया है।

### परिचय

- इस महीने 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के प्रारूप को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वह संसद की विशेष संयुक्त बैठक के साथ इस महत्वपूर्ण अवसर को मनाने का इरादा रखती है। हमारे विखंडित राजनीतिक विभाजन के सभी पक्षों से कई आत्म-प्रशंसापूर्ण भाषण होने ही हैं। लेकिन वह भाषण जो हम सभी को परेशान करना चाहिए, वह संविधान के प्रमुख प्रारूपकार, बी.आर. अंबेडकर का संविधान अपनाने की पूर्व संध्या पर दिया गया भाषण है।
  - 25 नवंबर, 1949 को, उन्होंने मसौदा समिति के काम का अपने शानदार सारांश में, जिसकी वे अध्यक्षता कर रहे थे, और विधानसभा के समक्ष इसके काम की सराहना करने से पहले, स्पष्ट रूप से कहा: "संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यह निश्चित रूप से बुरा साबित होगा, क्योंकि इसे लागू करने के लिए बुलाए गए लोग बुरे लोग होते हैं।"
  - संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, यह अच्छा साबित हो सकता है, अगर इसे लागू करने के लिए बुलाए गए लोग अच्छे लोग होते हैं।"
  - डॉ. अंबेडकर ने बताया कि संविधान का काम करना इस बात पर निर्भर करता है कि लोग और राजनीतिक दल इसे कैसे लागू करते हैं। प्रारूपकारों ने अपेक्षाकृत आसान संशोधन का प्रावधान किया था, ताकि दस्तावेज़ को समय की ज़रूरतों के हिसाब से बनाए रखा जा सके।
  - लेकिन बाकी सब इस बात पर निर्भर करता है कि इसके संरक्षकों की आने वाली पीढ़ियाँ इसे कैसे लागू करना चाहती हैं।

### बी.आर. अंबेडकर ने जिन कमियों की पहचान की

- डॉ. अंबेडकर ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि "भारतीय समाज में दो चीज़ों का पूर्ण अभाव है" - समानता और बंधुत्व।
- उन्होंने घोषणा की, "26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी।
  - राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को मान्यता देंगे।
- हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में, हम अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण, एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को नकारते रहेंगे।
- मुख्य प्रश्न: हम कब तक विरोधाभासों का यह जीवन जीते रहेंगे?



- हम कब तक अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे?"

### बंधुत्व का अभाव

- संविधान से एक सामाजिक और न केवल राजनीतिक लोकतंत्र के उभरने का आह्वान करते हुए, डॉ. अंबेडकर ने भारत में दूसरे प्रमुख तत्व के रूप में बंधुत्व के अभाव पर जोर दिया।
- "बंधुत्व का अर्थ है सभी भारतीयों के बीच समान भाईचारे की भावना - भारतीयों का एक होना। यह वह सिद्धांत है जो सामाजिक जीवन को एकता और एकजुटता प्रदान करता है।"
- लेकिन जाति व्यवस्था के कारण - उन्होंने कहा कि जाति की पूरी संरचना 'राष्ट्र-विरोधी' है - धार्मिक विभाजन और कुछ भारतीयों में राष्ट्रीयता की सामान्य भावना का अभाव, भाईचारा अभी तक हासिल नहीं हुआ था।
- लेकिन यह अपरिहार्य था, क्योंकि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित नहीं हो सकते थे।
- उन्होंने कहा, "समानता के बिना, स्वतंत्रता बहुत से लोगों पर कुछ लोगों की सर्वोच्चता पैदा करेगी। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को खत्म कर देगी।"
  - भाईचारे के बिना, स्वतंत्रता बहुत से लोगों पर कुछ लोगों की सर्वोच्चता पैदा करेगी।
  - भाईचारे के बिना, स्वतंत्रता और समानता चीजों का स्वाभाविक क्रम नहीं बन सकती।
- उन्हें लागू करने के लिए एक कांस्टेबल की आवश्यकता होगी।"

### क्या बदल गया है: 75 साल बाद डॉ. अंबेडकर का विजन और प्रगति

- आज, 75 साल बाद, यह पूछना उचित है कि संविधान के प्रारूपकारों के उद्देश्यों को प्राप्त करने और विशेष रूप से डॉ. अंबेडकर द्वारा पहचानी गई कमियों को पूरा करने के लिए हमने क्या प्रगति की है।
- इसमें कोई संदेह नहीं कि अस्पृश्यता के उन्मूलन के साथ-साथ दुनिया के सबसे पुराने और सबसे दूरगामी सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम, आरक्षण के रूप में, शुरू में अनुसूचित जातियों के लिए और फिर अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए, समानता आगे बढ़ी है।
- ये आरक्षण, जो शुरू में अस्थायी थे, अब हमारी व्यवस्था में जड़ जमा चुके हैं और कहा जा सकता है कि इन्हें राजनीतिक रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती।
- लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने का कार्य, जिसकी ओर डॉ. अंबेडकर ने इशारा किया था, अभी भी पूरा नहीं हुआ है।
- उन लोगों के लिए और अधिक अवसरों की मांग, जो मानते हैं कि भारतीय समाज उन्हें संख्याओं के आधार पर परिणामों की समानता से वंचित करना जारी रखता है, हमारी राजनीति को हिलाकर रख देता है।
- जाति जनगणना की बढ़ती मांग का भारत के संवैधानिक व्यवहार के विकास पर और भी प्रभाव पड़ना तय है।

### भाईचारे की स्थिति

## Daily News Analysis

- ➡ भाईचारे के मामले में, जाति, पंथ, क्षेत्र और भाषा के नाम पर हमारे विवादास्पद लोकतंत्र में वोटों की लामबंदी ने यह सुनिश्चित किया है कि डॉ. अंबेडकर ने जिस एकता की बात की थी, वह सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भावना अभी भी, सबसे अच्छे रूप में, प्रगति पर है।
- ➡ लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रवाद की भावना जो उन्होंने महसूस की थी कि अभी तक अस्तित्व में नहीं आई थी, अब पूरे देश में समाहित हो गई है।
- ➡ भारतीय टीम के साथ क्रिकेट मैच में भीड़ को देखने या कारगिल युद्ध (1999) या गलवान घटना (2020) जैसे अंतरराष्ट्रीय संघर्ष के बाद राष्ट्रीय आक्रोश और शोक को देखने से ही पता चल जाता है कि स्थानीय या सांप्रदायिक पहचानों के बने रहने के बावजूद राष्ट्रवाद की भावना मजबूत है।

### जाति आरक्षण और भाईचारा

- ➡ फिर भी, जाति आरक्षण को मूर्त रूप देकर, भारत ने समानता को बढ़ावा दिया है, लेकिन यकीनन भाईचारे को कमजोर किया है।
- ➡ डॉ. अंबेडकर की दृष्टि में बंधुत्व का विशेष स्थान था; यह शब्द कई मायनों में भारत के संवैधानिक विमर्श में उनका विशिष्ट योगदान था।
- ➡ इसका एक आर्थिक आयाम भी था, जिसमें निहित विचार यह था कि संपन्न लोगों की संपत्ति का उपयोग अछूतों और अन्य दुर्भाग्यपूर्ण लोगों के उत्थान के लिए किया जाएगा।
- ➡ बंधुत्व सामाजिक और जातिगत पदानुक्रमों के क्षरण का परिणाम होगा और उसे बढ़ावा देगा।
- ➡ लेकिन, जैसा कि समाजशास्त्री दीपांकर गुप्ता ने तर्क दिया है, ओबीसी को आरक्षण का विस्तार जाति को "एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संसाधन के रूप में देखता है जिसका हमेशा उपयोग किया जाना चाहिए"।
- ➡ प्रोफेसर गुप्ता का कहना है कि यह "बंधुत्व को बढ़ाने की भावना के अनुरूप नहीं है, जैसा कि अंबेडकर के प्रस्ताव हैं"; जबकि डॉ. अंबेडकर का अंतिम लक्ष्य भारतीय समाज से जाति का विनाश था, मंडल के लिए जाति को "हटाना" नहीं था, बल्कि "प्रतिनिधित्व" करना था।
- ➡ इसने जाति को सार्वजनिक जीवन से खत्म करने के बजाय उसे और मजबूत किया।

### उच्च और चिंताजनक निम्न

- ➡ यह बहस जारी रह सकती है।
- ➡ फिर भी, हम आभारी हो सकते हैं कि भारतीय राजनीति के उन्हीं तत्वों के सत्ता में आने के बाद, जिन्होंने शुरू में संविधान को अस्वीकार कर दिया था, संविधान को त्यागने की नौबत नहीं आई।
- ➡ भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा उस दस्तावेज का जश्न मनाना एक विडंबना है, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के उसके पूर्वजों ने "अभारतीय" और आत्मा से रहित पाया था।
- ➡ वह आत्मा 75 वर्षों और 106 संशोधनों के दौरान विकसित हुई है, और संविधान अभी भी फल-फूल रहा है।
- ➡ लेकिन संविधान द्वारा निर्मित कई संस्थाओं का खोखला होना, संसद का कमजोर होना, न्यायपालिका पर दबाव और लोकतांत्रिक भावना को कमजोर करना - जिसके कारण वी-डेम संस्थान ने भारत को "चुनावी निरंकुशता" के रूप में

## Daily News Analysis

लेबल किया, जिसकी निगरानी "कांस्टेबल" डॉ. अंबेडकर ने की थी - इसका मतलब है कि इसके संरक्षकों द्वारा अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

### निष्कर्ष

- ▶ डॉ. अंबेडकर ने अपने यादगार भाषण के समापन में कहा, "स्वतंत्रता निस्संदेह खुशी की बात है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस आज़ादी ने हम पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ डाल दी हैं।
- ▶ आज़ादी के साथ ही, हमने किसी भी ग़लती के लिए अंग्रेजों को दोषी ठहराने का बहाना खो दिया है। अगर भविष्य में कुछ ग़लत हुआ, तो हमें खुद को छोड़कर किसी और को दोषी नहीं ठहराना होगा।
- ▶ पचहत्तर साल बाद, आइए हम उन चीज़ों की संख्या कम करने की कसम खाएँ जिनके लिए हमें खुद को दोषी ठहराने की ज़रूरत है - और संविधान हमें रास्ता दिखाए।

